Benefits of concessional power in rural areas

994. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that benefits of concessional power in rural areas is confined to a limited number of people;

(b) whether it is also a fact that Government propose to carry out a survey in this regard and if so, by what time;

(c) whether it is also a fact that Government propose to rationalise the supply of power at concessional rates in rural areas; and

(d) if so, by when and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) No, Sir. About 84 per cent of the villages in the country have already been elctrified, while about 28 per cent of the total sale of electricity by SEBs is accounted for by the agricultural sector, which fetches an average realisation of only 12.58 P/kwh.

(c) and <d) The tariff for supply of electricity to the different sectors of consumers is fixed by the SEBs/State Govts, concerned. The Power Ministers' Conference held in January, 1993 had adopted an Action Plan to fix the minimum agricultural tariff of 50 P/kwh.

नाथपा झाकरी में पन बिजली परियोजना

995. **श्री शांति त्यागी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाथपा झाकरी में 1500 मेगावाट क्षमता वाली पन-बिजली परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है और यह योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी, और

(ग) इस परियोजगा के पूरा होने पर विद्युत का वार्षिक उत्पादन कितना होगा और बाद में इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) (क) और (ख) भारत सरकार ने 4337.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों वाली नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना (6X250= 1500 मे०वा०) के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को दिसम्बर, 1998 तक चालू कर दिए जाने की प्रत्याशा है ।

(ग) इस परियोजना से 90% विश्वसनीय वर्ष में 6700 मिलियन यूनिट वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की प्रत्याशा की गई है जिसमें से 1500 मेगावाट व्यस्ततमकालीन विद्युत उत्तरी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाएगी । इससे कालान्तर में पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह परियोजना एक सरित-प्रवाही स्कीम है जिसके अन्तर्गत केवल 60 मीटर ऊंचे विपथन बांध का निर्माण किया जाना है जिससे किसी प्रकार का जल अवरोध नहीं होगा । तद्नुसार, पारिस्थितिकी, जनसंख्या का विस्थापन तथा वनों की कटाई संबंधी समस्यायें बहुत ही कम होने की प्रत्याशा है ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट

996. **श्री शांति त्यागी** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट का प्रमुख कारण अनपारा-बी और अनपारा-ए के विद्युत गृहों का चालू न होना है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कुछ सप्ताह पूर्व केन्द्रीय सरकार का ध्यान इन दोनों विद्युत गृहों को शीघ्र चालू कराने और अनपारा-उन्नाव तथा अन.पारा-गोरखपुर की ट्रांसमिशन लाइनों के बिछाने की ओर दिलाया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री) पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ग) अनपारा "क" (3X210 मे०वा०